



किसी भी तरह के विज्ञापन एवं समाचार के लिए संपर्क करें मो: ९८९१७०६८५३

दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

RNI: UPHIN/2021/84200

समाज जागरण

नोएडा उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड असम से प्रसारित



वर्ष: ३ अंक: 213 नोएडा, (गौतमबुद्धनगर) शनिवार 17 मई 2025

<http://samajjagran.in>

पृष्ठ - 12 मूल्य 05 रुपया

NOTAM जारी, आयत करेगा घातक मिसाइल टेस्ट !

अंडमान की लहरों से उठेगा ब्रह्मोस का तूफान ?

नई दिल्ली: 23-24 मई तारीखे तय हैं और जगह भी, अंडमान और निकोबार की लहरों के बीच भारत एक बार फिर मिसाइल शक्ति का दम दिखाने जा रहा है। अगर मिसाइल टेस्ट हुआ तो यह उन देशों को चेतावनी होगा जो भारत की सहनशीलता को कमज़ोरी समझ बैठे हैं भारत सरकार ने इस तारीख को NOTAM जारी किया है। यह एक वैधानिक सुचना होती है, जो उड़ानों को उस क्षेत्र से दूर रहने का अलाई देती है क्योंकि वहाँ कोई बड़ा सैन्य या वैज्ञानिक परीक्षण होने वाला है। और जब बात अंडमान की हो, तो समझ जाइए... बात ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल की हो सकती है।

ब्रह्मोस: भारत की 'पैन चेतावनी'

ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं

भारत ने 23-24 मई 2025 के लिए एक नोटिस टू एयरफोन जारी किया है, यह NOTAM अंडमान और निकोबार द्वापर समूह के आसपास जारी किया गया है।



है, ये आवाज से लगभग तीन गुना तेज़ चलती है और दूरमन को संभलने तक का मौका नहीं देती। भारत और रूस की संयुक्त कानूनीक से बनी ये मिसाइल जमीन, हवा और समुद्र... तीनों से दागी जा सकती है। इसकी रेंज अब 900 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, यानी दूरमन के दिल में उतरने की काविलियत रखती है।

आयत ने दियाया बड़ा दिल,

अफगानी ट्रकों के लिए एयोला अटाई-बाधा बॉर्डर, लेकिन पाकिस्तान ने फिर दिया दी ओकात

ट्रेडर्स को होता भारी नुकसान

अमुतसर के सूखे मेवे के ट्रेडर्स मुकेश शिवायी ने कहा, "रूट के बंद होने के कारण सामान की गुणवत्ता खराब हो रही थी। भारतीय आयत के अफगान ट्रेडर्स मेंटर करते हैं। अगर यह रूट फिर से नहीं खुलता, तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता,"

तालिबान के साथ भारत के नए कूटनीतिक संबंधों का आगाज तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने 16 मई को कहा, "अफगानिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को फिर से सामान्य बनाने और देश के विकास के लिए निवेश को आमंत्रित करने की कोशिश कर रहा है।" यह बयान तब आया जब विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान के एकटिंग विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी से गुरुवार को बातचीत की। यह भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के बीच मंत्री स्तर की पहली बातचीत थी।

एयर इंडिया ने सरकार से इंडिगो के तुर्की एयरलाइन्स के साथ लीज को खल्क करने के लिए पैट्रोट

एयर इंडिया ने सरकार से तुर्की एयरलाइन्स के साथ लीज के लिए अनुमति प्राप्त एकमात्र लैंड लिंक है। इस बात की पुष्टि करते हुए इंडिगो के लीजिंग गर्डोड को रोकने पर इन ट्रकों की मंजूरी को रोक रखा है। इसके लिए उसने व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ-साथ इस्तांबुल द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने से उत्पन्न सुरक्षा और अफगानिस्तान की सरकारों का धन्यवाद करते हैं।

भारत पहुंचे। यह भारत और दी। लेकिन, लोगों ने बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी बांडर पर इन ट्रकों की मंजूरी को रोक रखा है।

इंडो-फॉरेन चैंबर ऑफ कॉर्मर्स के प्रेसिडेंट ने की पुष्टि आधिकारिक सूतों के मुताबिक, दोपहर में सूखे मेवे ले जा रहे 8 ट्रक 24 अप्रैल से लाहौर और वायां बांडर के बीच फंसे हुए ट्रकों में से थे।

भारतीय अधिकारियों ने स्पेशल गेस्चर के रूप में करीब 150 अफगान ट्रकों को सूखे मेवे और रखती है।

भारत और दी। लेकिन, लोगों ने बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी बांडर पर इन ट्रकों की मंजूरी को रोक रखा है।

इंडो-फॉरेन चैंबर ऑफ कॉर्मर्स के प्रेसिडेंट ने की पुष्टि आधिकारिक सूतों के मुताबिक, दोपहर में सूखे मेवे ले जा रहे 8 ट्रक अटारी-वाया बांडर पर करते हैं।

उन्होंने प्रस्तुत की तुर्की की ग्रांड हैंडिंग सेवा फम सेवी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी।

पहले नमाईफाए.. फिर हुनरे पर बैठ जॉर्जिया मेलोनी का स्थान

तिराना: अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित यूरोपीय राजनीतिक समुदाय की बैठक में एक ऐसे दृश्य देखने को मिला, जिसने कूटनीति की दुनिया में गर्मजोशी और रंग भर दिए। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने यूरोप के 40 से अधिक नेताओं का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया कि हर कैमरा और हर आंख उन पर टिक गई। बारिश के बीच रामा नीली छतरी लेकर, EPC लोगों लगी

शशि थर्सर, असदुद्दीन ओवैसी चर्चाने की सूची में आपनी धरती पर पाकिस्तान की संपर्क नेताओं को बताया कि कार्यसांसद शशि थर्सर और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। शशि थर्सर, जो भारत में विदेश मामलों पर समर्दीय पैनल के प्रमुख भी है, प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर सकते हैं। शशि थर्सर और ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर समर्थन किया है, जिसमें भारतीय रूप से सेने की परिस्थितियों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुआ। यह पिछले रिपोर्टिंग सत्राह से उलट है, जब भंडार 2.065 बिलियन डॉलर घटकर 686.064 बिलियन डॉलर रह गया था। एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2024 के अंत में भंडार 704.885 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड 17 अंच स्तर पर पहुंच गया था। समीक्षाकारी सताह के दौरान, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां - विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक - 196 मिलियन डॉलर की मामूली वृद्धि

नई दिल्ली: शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9 मई को समाप्त सप्ताह के लिए 4.553 बिलियन डॉलर बढ़कर 690.617 बिलियन डॉलर हो गया, जो मुख्य रूप से सेने की परिस्थितियों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुआ। यह पिछले रिपोर्टिंग सत्राह से उलट है, जब भंडार 2.065 बिलियन डॉलर घटकर 686.064 बिलियन डॉलर रह गया था। एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2024 के अंत में भंडार 704.885 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड 17 अंच स्तर पर पहुंच गया था। समीक्षाकारी सताह के दौरान, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां - विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक - 196 मिलियन डॉलर की मामूली वृद्धि



टाई और स्नीकर्स में हर नेता को व्यक्तिगत एडी रामा का उत्साह जरा भी नहीं टूटा।

उन्होंने प्रस्तुत की तुर्की की ग्रांड हैंडिंग सेवा की शुरुआत। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां तब बटोरी जब उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के सामने घुटनों पर बैठकर उनका स्वागत किया।

बैठक के दिन अचानक बारिश शुरू हो गई लेकिन उन्होंने तक सीमित नहीं बल्कि दिल से दिल जोड़ने की कला भी है।

इस बीच, विशेष आहरण अधिकार (एस-डीआर) में \$26 मिलियन की गिरावट आई, जो \$18.532 बिलियन पर आगया। आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति में भी \$13.4 मिलियन की कमी देखी गई, जो रिपोर्टिंग सताह के दौरान \$4.374 बिलियन पर आगई।

देश के केंद्रीय बैंक द्वारा बनाए गए ये विदेशी मुद्रा भंडार मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख आरक्षित मुद्राओं में रखे जाते हैं, जबकि ये, जापानी बैंक और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में छोटे आवंटन होते हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार बैंकर और घरेलू बैंकों द्वारा बनाए गए ये रखे जाते हैं, जबकि ये अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख शहरों के बाजारों में सक्रिय रूप से तरलता का प्रबंधन करता है।

इसके लिए ये रखे जाते हैं, जबकि ये अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख शहरों के बाजारों में सक्रिय रूप से तरलता का प्रबंधन करता है।

इसके लिए ये रखे जाते हैं, जबकि ये अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख शहरों के बाजारों में सक्रिय रूप से तरलता का प्रबंधन करता है।

इसके लिए ये रखे जाते हैं, जबकि ये अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख शहरों के बाजारों में सक्रिय रूप से तरलता का प्रबंधन करता है।

इसके लिए ये रखे जाते हैं, जबकि ये अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख शहरों के बाजारों में सक्रिय रूप से त

एष्ट्रीय एकता सभ्यते ऊपर

ऑपरेशन सिंदूर को इतिहास एक ऐसे अवसर के स्वरूप में गी याद किया जाना चाहिए जिसने देश को आने वाले समय के लिए एकजुट किया।

बोते करीब तीन सप्ताह में जो कुछ घटित हुआ है वह देश के समकालीन इतिहास में विशिष्ट स्थान पाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। हालांकि हमले के वास्तविक आरोपी नहीं

OPERATION SINDOOR

पकड़े जा सके हैं लेकिन सुरक्षा बलों के पास यह पत लगाने के पर्याप्त प्रमाण थे कि इसका संबंध पाकिस्तान और पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों से था। इस घटना ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। विपक्षी दलों ने भी सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि वह जो उचित समझी वह कदम उठाए। 6-7 मई की दरमायीन रात भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरूआत की और पाकिस्तान तथा पाक के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में 9 स्थानों पर आतंकी ठिकानों पर हमला किया। यह सैन्य कार्रवाई निर्मला-तुला, स्टार्ट निशाने पर और बिना उकासवे वाली थी। बहरहाल पाकिस्तान ने हालात बिगाड़ने शुरू कर दिए और भारतीय सैन्य बलों को जवाब देना पड़ा। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में सैन्य परिसंपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया। चूंकि भारतीय सैन्य बलों ने आरंभिक लक्ष्य हासिल कर लिया था इसलिए भारत ने पाकिस्तान की अपील पर कार्रवाई को स्थगित करने का निर्णय लिया।

22 अप्रैल के बाद से घटित सभी घटनाओं का खूब विशेषण किया जा रहा है और उन पर चर्चा भी हो रही है। यह मानना सही है कि सुरक्षा प्रतिष्ठान भी हर पहलु का आकलन कर रहा है ताकि अगर कोई कमी है तो उसे दूर किया जाए। इसके अलावा भविष्य को लेकर भी पूरी तैयारी रखनी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सशस्त्र बलों की कामयादी के अलावा भारत ने जबरदस्त राष्ट्रीय एकता की भी प्रदर्शन किया है। यह याद करना अचित होगा कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मृतकों को उनकी धार्मिक पहचान की पुष्टि करने के बाद मार गया था।

अब यह बहुत व्यापक तौर पर मानी जा रही है कि अन्य लक्ष्यों के अलावा हमले का इरादा देश में सांप्रदायिक तनाव भड़काना भी था। परंतु यह करार नहीं हुआ। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में भी कहा, ह्यूम्यू देश, हर नागरिक, हर समुदाय, हर वर्ग एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ ठोका कार्रवाई के लिए खड़ा रहा है। हालांकि, दुर्भाग्यवश कुछ लोग नहीं चाहते कि यह एकता बरकरार रहे। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के एक महिला सैन्य अधिकारी को लेकर एक अपमानजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी की। इस अधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को जानकारियां दी थीं। हालांकि अदालतों ने इस मामले का संज्ञान लिया है और कानूनी कदम उठाया जा चुका है लेकिन जरूरत है एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने की। राज्य सरकार और राजनीतिक नेतृत्व को यह दिया देना चाहिए कि ऐसी हरकतों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।

दुर्भाग्यवश मंत्री ने जो कुछ कहा है वह एक विभाजनकारी राजनीति और समाज की प्रतिविमूँ है और यह अपनी तरह की कोई इकलौती घटना नहीं है। पहलगाम आतंकी हमलों में मगेर ए नेसना अधिकारी की पत्री को उस समय ऑनलाइन ट्रोल किया गया जब उन्होंने कहा था कि मुसिलिमों या कश्मीरियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री और उनके परिवार, खासका उनकी बेटी को भी ऑनलाइन ट्रोल किया गया। ट्रोल करने वालों को मिश्री की बेटी के पेशेवर काम में सांप्रदायिक दृष्टिकोण मिल गया। देश की सार्वजनिक बहस में ऐसी बातें स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। देश ने वो बोते कुछ हफ्तों में जो एकजुटा दिखाई है उसे बचाने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर को इतिहास में केवल एक सैन्य कामयादी के रूप में नहीं दर्ज होना चाहिए। इसे एक ऐसे अवसर के रूप में भी याद किया जाना चाहिए जिसने देश को आने वाले समय के लिए एकजुट किया। अब यह सभी दलों के राजनीतिक नेतृत्व पर निर्भर है कि वे चुनावी लाभ के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक राजनीति से दूर रहें और भारतीय राज्य को भी ऐसी विभाजनकारी बातों को बर्दाशत नहीं करना चाहिए। इससे देश में सोहाइट बढ़ेगा और अधिक विकास में जेजी आएगी।

अब सुप्रीम कोर्ट से यास्त्रपति नुर्मू की गिड़त

समाज जागरण



लगता है कि सरकार और भाजपा के बड़े नेता सुप्रीमकोर्ट को चैन से नहीं बैठने देंगे। सुप्रीमकोर्ट से पहले भाजपा सांसद निश्चिकत दुबे और बाद में उपराष्ट्रपति जर्वीप धनकड़ ने मुठभेड़ की थीं। दुबे ने सीजे-आर्ट को देश में चल रहे तमाम गुद्युओं के लिए जिम्मेदार ठहराया था और धनकड़ ने राज्यपालों के अधिकारों को समीक्षित करने पर आपत्ति जताई थीं। अब राष्ट्रपति द्वारा पूर्ण मुर्मू ने भी सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के ऐसेतिहासिक फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, राष्ट्रपति ने इस फैसले को संवेदनानिक मूल्यों और व्यवस्थाओं के विपरीत बताया और धनकड़ को देश में राज्यपाल के अधिकारों को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राज्यपाल को एक महीने में उसकी स्वीकृति देनी होगी। यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के वास्तव में भेजा गया हो तो राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने श्रीमती द्वोपदी मुर्मू ने इस फैसले को संवेदनानिक व्यवस्था के विपरीत बताया और कहा

कि अनुच्छेद 200 और 201 में ऐसा कोई समय-दिलाइए चुना व्यक्ति उन्हें लगता है कि समीक्षा व्यावधान की अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से 14 संवेदनानिक प्रश्नों पर राष्ट्रपति ने कहा था कि वास्तव में धनकड़ ने इसे फैसले के बाद राष्ट्रपति के विवेकाधीन निर्णय दिया और सकारात्मक परिणाम की संभावना कर रहा है।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को देश में राष्ट्रपति या राज्यपाल के विवेकाधीन निर्णय के लिए किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक वास्तव में राष्ट्रपति ने संवेदनानिक व्यवस्था को पूर्ण न्याय करने का अधिकार मिलता है। राष्ट्रपति ने कहा कि जहां एकरूपता, राष्ट्र की सुरक्षा और शक्तियों के प्रयोग पर भी सावधान रहा है, तो उसे भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने कोई विधेयक के बाद राष्ट्रपति को भी तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

राष्ट्रपति ने को

